

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास- दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

म्यूटेशन अपील संख्या -14/2016

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स
1. शंकरराम पुत्र हरदीनराम		1. उपखण्ड अधिकारी मेड़ता।
2. किशनाराम पुत्र हरदीनराम		2. राजस्थान राज्य जरिये
जाति जाट, निवासी इन्दावड़,		तहसीलदार भूअभिलेख मेड़ता
तहसील मेड़ता, जिला नागौर		सिटी, जिला नागौर
		3. ग्राम पंचायत इन्दावड़ पंचायत
		समिति मेड़तासिटी
		4. मंगलाराम पुत्र हरदीनराम
		5. पप्पुराम पुत्र पांचाराम
		6. छोटूराम पुत्र हरदीनराम
		7. हेमाराम पुत्र रामूराम
		जाति जाट, निवासी इन्दावड़,
		तहसील मेड़ता, जिला नागौर

उपस्थिति:-

1. अपीलाण्ट्स की ओर से वकील श्री धर्मराम खुड़खुड़िया।
2. रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 से 2 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय

दिनांक 04-02-2019

अपीलांट ने यह अपील 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। अपीलान्ट द्वारा ग्राम इन्दावड़ तहसील मेड़ता के खसरा नम्बर 2522 के संबंध में म्यूटेशन संख्या (3572)1097 जो तहसीलदार मेड़ता द्वारा दिनांक 5.5.2011 को स्वीकृत किया गया है, से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 28.01.2016 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील ताबे उच्च मियाद दर्ज रजिस्टर कर, अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया व रेस्पोडेण्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या-3 से 7 ने प्रकरण की सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

वकील अपीलान्टस् ने मियाद प्रार्थना पत्र के संबंध में अपनी बहस में कथन किया कि उपरोक्त विधि विरुद्ध म्यूटेशन की कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी न ही अपीलान्ट की उपस्थिति में नामान्तरकरण भरा गया, न कोई नोटिस दिया न ही नामान्तरकरण हेतु जो विधिक प्रक्रिया होती है उसकी पालना की, अपीलान्ट को सर्वप्रथम नामान्तरकरण जैर अपील की जानकारी दिनांक 06.01.2016 को हुई। जिससे अपील अपीलान्ट अन्दर मयाद शुमार करने योग्य होने का कथन करते हुए न्याय हित में अपील पेश करने में हुई देरी को उपरोक्त माकूल व पर्याप्त कारण को देखते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया। राजपैरोकार ने अपीलान्ट की अपील मयाद बाहर होने का कथन करते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया। अपीलान्ट द्वारा

A
7/1/19
कलक्टर, नागौर



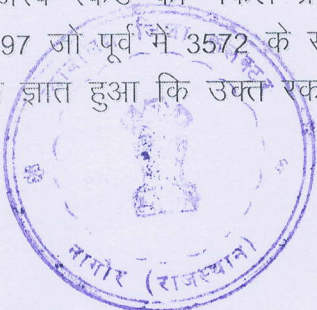
अपील के साथ प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर सहानभूतिपूर्वक विचार करते हुए न्यायहित में इस अपील का गुणावगुण के आधार पर सुनवाई कर निर्णय पारित किया जाना उचित है। अपीलान्त की अपील पर मेरिट पर सुनवाई की गई।

वकूलाय की बहस अंतिम सुनी गई। वकील अपीलान्त ने स्वयं की बहस में कथन किया की ग्राम इन्दावड़ में साबिका खसरा नम्बर 817 करीब 8 बीघा पर अपीलांट्स के पूर्वजों का रिहायसी बाड़ा, ढाणी, ऐवाड़ा रहता आया था जो जागीर समय से रहता आया था। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रभाव में आने से पहले ही उक्त बाड़े पर अपीलांट के व रेस्पोंडेंट्स संख्या 3 से 6 के पूर्वजों के रिहायसी बाड़ा, ढाणी रहते आये थे व आपसी बंटवाड़े में संवत् 2020 के आस पास अपीलांट्स के तन्हा बंट में रहती आई है। उक्त भूमि के एक तरफ पुरानी इस्तेमाली नाडी की नीचे की पाल (पानी को रोकने हेतु रेत की भूतल से 10-12 फुट उंचाई तक रेत इकट्ठी कर बनाई हुई पाली) रहती आई है तथा उक्त ढाणी के एक तरफ आम रास्ता तथा अन्य दो दिशाओं में से एक दिशा में रिहायशी ढाणियां व एक और दिशा में रास्ता रहता आया है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रभाव में आने के बाद कभी कभी पटवारियों ने उक्त रिहायसी ढाणी का उल्लेख गिरदावरीयों में व खसरा परिवर्तनशील में दर्ज किया व कभी नहीं किया तथा उक्त 8 बीघा रकबा के चिपती हुई आबादी रहती आई है। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि व ग्रामवासी उक्त भूमि को आबादी में होना महसूस कर रहे हैं तथा राजस्व विभाग के कर्मचारी भी कभी आबादी की भूमि होना व कभी राजस्व भूमि होना आभाष करने से जिन पटवारियों ने इसे आबादी सीमा में होना स्वीकार किया उन्होंने गश्त गिरदावरी में उल्लेख नहीं किया व जिन राजस्व पटवारियों ने इसे राजस्व भूमि माना उन्होंने गश्त गिरदावरीयों में अपीलांट संख्या 1 का नाम दर्ज किया है। तहसील मेड़ता में सन 2000 के बाद से प्रथम भूप्रबंध की कार्यवाही शुरू हुई जो सन् 2004 के आस पास खत्म हुई व भूप्रबंध अधिकारियों ने उक्त भूमि को राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 2522 होना व अलग खसरा व रकबा होना अंकित किया है तथा जिस तरफ पाल है उस तरफ पाल के खसरा नम्बर 2519 व तालाब के पानी इकट्ठा होने के रकबे को 2520 दर्ज किया है।

हाल खसरा नम्बर 2522 का सम्पूर्ण रकबा अपीलांट व रेस्पोंडेंट संख्या 3 से 6 के पूर्वजों के कब्जे व स्वामित्व, हक अधिकार का रहता आया है व वर्तमान में भी आपसी बंटवाड़े में अपीलांटान के बंट में है। सन् 1988 के आस पास उक्त भूमि को खसरा नम्बर 817 व 819 होना मानते हुए पटवारी हल्का ने 10 बिस्वा भूमि पर अपीलांट संख्या 1 को अतिक्रमी होना मानते हुए उस पर बाड़ा होना दर्ज करते हुए तहसीलदार को रिपोर्ट पेश की जिस पर मुकदमा नंबर 88/10 दिनांक 6.9.2010 को दर्ज किया व तत्पश्चात् पटवारी हल्का ने भूमाप करने पर उक्त भूमि आबादी में स्थित होना प्रतिष्ठत हुआ तब पुनः पटवारी ने अपनी त्रुटि को सुधारते हुए वास्तविक तथ्य तहसीलदार के सामने रखे तब माननीय तहसीलदार ने दिनांक 13.09.2010 को पुनः निर्णय करते हुए कार्यवाही आबादी में स्थित भूमि बाबत होना स्वीकारते हुए खारिज करने का आदेश पारित किया व आज दिन तक अपीलांटान काबिज है उक्त आदेश के विरुद्ध अलग से अपील पेश की जा चुकी है नामान्तरकरण के विरुद्ध यह अपील पेश की जा रही है।

हाल ही में गांव में चर्चा हुई कि अपीलांट के उक्त कब्जे को ग्राम पंचायत के वर्तमान निर्वाचित सरपंच व पंचगण कार्यवाही कर कब्जा हटाने की तैयारी कर रहे हैं तब अपीलांटान ने राजस्व रेकॉर्ड की नकले प्राप्त की तब दिनांक 6.1.2016 को अपीलांटान के नामान्तरकरण संख्या 1097 जो पूर्व में 3572 के स्थान पर दर्ज किये गये हैं, की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई व अपीलांट को ज्ञात हुआ कि उक्त रकब की किस्म आबादी की बजाय पुनः खसरा नम्बर 2522 की किस्म गेर

शंकरराम वगैरह



मुमकिन गौचर गलत दर्ज कर दी है। म्यूटेशन जैर अपील विधि विरुद्ध अनुचित व क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर सुनवाई का अवसर दिये बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना पारित किया गया है जो निरस्त किया जाने योग्य है।

ग्राम इन्दावड़ तहसील मेड़ता में भूप्रबंध की कार्यवाही हो चुकी है व भूप्रबंध अधिकारी द्वारा खसरा नम्बर 2522 को गेर मुमकिन आबादी दर्ज कर दिया गया था व मौके पर भी आबादी के उपयोग में हो रही भूमि की किस्म को उपखण्ड अधिकारी द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किस्म परिवर्तन का जो आदेश दिया है। विधि विरुद्ध व त्रुटिपूर्वक होने से उसके विरुद्ध अलग से अपील सक्षम न्यायालय में पेश की जा चुकी है, म्यूटेशन हाजा के विरुद्ध न्यायालय हाजा में यह अपील पेश की गई।

रेसपो. सं. 4 से 7 को पुश्तेनी स्वामित्व के कब्जे काश्त होने व अपीलांतान को बंट में दी जाने के अभिवचन होने से आवश्यक पक्षकार के रुप दर्ज करना आवश्यक होने से पक्षकार दर्ज कर अपील पेश की गई है, का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नामान्तरण जैर अपील निरस्त करने का निवेदन किया है।

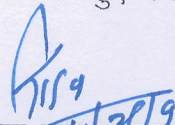
राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने स्वयं की बहस में कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में म्यूटेशन जैर अपील उपखण्ड अधिकारी मेड़ता के आदेश 20.3.11 एवं तहसीलदार मेड़ता के आदेश 29.3.2011 की पालना में पटवारी इन्दावड़ द्वारा भरा गया है, जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक गगराना ने जाँच में सही पाया जाने की रिपोर्ट अंकित की है। उक्त आधार पर तहसीलदार मेड़ता द्वारा म्यूटेशन जैर अपील स्वीकृत किया है, जो सही है। तहसीलदार मेड़ता द्वारा उक्त म्यूटेशन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता के आदेश की पालना में स्वीकृत गया है, जो विधि सम्मत होने का कथन करते हुए राजपैरोकार ने अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में म्यूटेशन जैर अपील उपखण्ड अधिकारी मेड़ता के आदेश क्रमांक 563 दिनांक 20.3.11 एवं तहसीलदार मेड़ता के आदेश क्रमांक 727 दिनांक 29.3.2011 की पालना में पटवारी इन्दावड़ द्वारा भरा जाकर भू अभिलेख निरीक्षक गगराना के समक्ष प्रस्तुत किया, भू अभिलेख निरीक्षक गगराना ने जाँच में सही पाया जाने की रिपोर्ट म्यूटेशन जैर अपील पर दिनांक 19.04.2011 को अंकित की किये जाने पर तहसीलदार मेड़ता द्वारा उक्त म्यूटेशन उपखण्ड अधिकारी मेड़ता के आदेश दिनांक 20.3.11 की पालना में स्वीकृत किया गया है, जो विधि सम्मत है। अपीलांट्स यदि उक्त आदेश दिनांक 20.03.2011 से असंतुष्ट है तो वह सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। इस प्रकार किसी न्यायालय के आदेश की पालना में स्वीकृत किये गये म्यूटेशन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना विधि सम्मत नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय सुनाया।




(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलेक्टर, नागौर
